



### भारतीय अर्थव्यवस्था: एक पड़ताल

रवींद्र एच ढोलकिया



सभी ताकतों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम से दीर्घावधि में 8 से 10 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की संभावना है। इसी कारण इस समय भारत में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल सभी समतुल्य एवं प्रतिस्पर्द्धी देशों की अपेक्षा सर्वाधिक आकर्षक है। समीक्षा में अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण ताकत छूट गयी है कि भारत में सभी स्तरों पर पूर्णतया स्वीकृत लोकतंत्र रहा है, जिसमें अच्छी तरह विकसित संस्थाएं हैं और जनता की व्यापक सहभागिता वाला प्रशासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खूबी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है

**सं** सद में 31 जनवरी, 2017 को पेश की गयी आर्थिक समीक्षा 2016-17 हाल के घटनाक्रमों को केंद्र में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन प्रस्तुत करती है। यह गहन शोध तथा अनुभवजन्य प्रमाणों के साथ तर्क प्रस्तुत कर समस्याओं, चुनौतियों, संभावित समाधानों तथा संभावनाओं का विश्लेषण करती है। यह बड़ी कवायद होती है, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं तथा विद्वानों का योगदान होता है। पिछले दो वर्षों से उलट इस वर्ष समीक्षा को केवल एक भाग में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के व्यापक आकलन वाला दूसरा भाग बाद में अलग से लाने की योजना है। इसलिए समीक्षा में वर्तमान साहित्यिक अध्ययनों, प्रिंट तथा दृश्य मीडिया में आई टिप्पणियों तथा सरकारी विभागों एवं शोध संस्थानों में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से किए गए नए शोधों की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकतों, कमजोरियों, अवसरों तथा खतरों के विश्लेषण, जिसे एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण भी कहते हैं, पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान आलेख ताकतों, कमजोरियों, अवसरों तथा जोखिमों की श्रेणियों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सामने आ रहे विशिष्ट बिंदुओं पर संक्षेप में विचार कर रहा है।

#### ताकत

1. निराशा भरे वैश्विक आर्थिक वातावरण एवं व्यापक मंदी के बीच भी भारतीय

अर्थव्यवस्था प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ चमक बिखेरती है। हालांकि समीक्षा 2016-17 के दौरान 6.5 से 6.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त कर रही है, लेकिन मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का अनुमान है कि यह 7 प्रतिशत के आसपास रहेगी, जिससे देश विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुद्रास्फीति की दर लगभग 4 से 5 प्रतिशत है और कम हो रही है। भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत से भी कम है और डॉलर तथा रुपये की विनिमय दर लगभग स्थिर है। विदेशी ऋण सुरक्षित सीमा के भीतर है और पिछले दो वर्षों से केंद्र तथा राज्य सरकारें राजकोषीय अनुशासन और सुदृढीकरण की जिस राह पर चल रही हैं, उसमें उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के साथ और उसके बगैर भी किसी तरह की ढिलाई की संभावना नहीं है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार के उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हो। 2015-16 में यह जीडीपी का 1.7 प्रतिशत था, जो 2016-17 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 3.2 प्रतिशत तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2016 तक बढ़कर 360 अरब डॉलर हो गया, जो भंडार की पर्याप्तता के मानक नियमों को पूरा करता है।

लेखक वर्ष 1985 से आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। भारत सरकार द्वारा गठित कई उच्च स्तरीय समितियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मौद्रिक नीति समिति के भी सदस्य हैं। भारत सरकार के छोटे वेतन आयोग (2006-08) के भी सदस्य रह चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 140 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा 22 पुस्तकें और 47 मोनोग्राफ भी लिख चुके हैं। ईमेल: rdholkia@iima.ac.in



3. थोक मूल्य सूचकांक तथा खुदरा मूल्य सूचकांक द्वारा नापी जाने वाली मुद्रास्फीति की दरों के बीच 2015-16 में मौजूद बड़ा अंतर अब भरा जा चुका है और अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक मूल्य अब काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं। इसके कारण सांकेतिक जीडीपी में वृद्धि भी बहाल हो गयी है, जो सरकार की राजस्व वृद्धि को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. अधिक मूल्य वाले नोटों के सफल विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार में कमी, घरेलू वित्तीय बचत में वृद्धि तथा कर का दायरा बढ़ने जैसे दीर्घकालीन लाभ होने की संभावना है।

5. वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और इसके क्रियान्वयन से पूरे देश में एक ही बाजार बन जाएगा। कर का बेहतर अनुपालन होगा निवेश तथा वृद्धि में तेजी आएगी और अच्छे प्रशासन के तरीके अपनाए जाएंगे।

6. विश्व के विनिर्माण निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ रहा है क्योंकि पूंजी की अधिक आवक और उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद देश प्रतिस्पर्द्धी रहा है।

7. भारत में अंतरराज्यीय व्यापार के कारण वस्तुओं की आंतरिक आवाजाही जीडीपी की लगभग 54 प्रतिशत अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की 1.7 गुना है। इसी प्रकार कामकाज के कारण प्रवास भी बहुत अधिक है।

8. पेट्रोलियम और डीजल पर कर लगाकर भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रतिबद्धता के मामले में अधिकतर देशों को पछाड़ दिया है।

9. जनांकिकी के मामले में भारत को दूसरे समतुल्य देशों की अपेक्षा बहुत प्राप्त है। विभिन्न बड़े राज्यों के जनांकिकी संबंधी अलग-अलग चरित्र यह सुनिश्चित करेंगे कि देश दूसरे अन्य देशों की तुलना में अपने चरम पर अधिक समय तक रहेगा।

10. लक्षित समूहों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सीधे एवं प्रभावी रूप से पहुंचने के लिए देश में जैम- जन धन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल फोन द्वारा

बहुत व्यापक नेटवर्क एवं बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।

11. देश में समय बीतने के साथ सभी राज्यों में जीवन प्रत्याशा तथा प्रजनन दरों जैसे स्वास्थ्य संबंधी परिणाम एक दूसरे के समान हो रहे हैं।

12. सभी ताकतों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम से दीर्घवधि में 8 से 10 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की संभावना है। इसी कारण इस समय भारत में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल सभी समतुल्य एवं प्रतिस्पर्द्धी देशों की अपेक्षा सर्वाधिक आकर्षक है।

समीक्षा में अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण ताकत छूट गयी है कि भारत में सभी स्तरों पर पूर्णतया स्वीकृत लोकतंत्र रहा है, जिसमें अच्छी तरह विकसित संस्थाएं हैं और जनता की व्यापक सहभागिता वाला प्रशासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खूबी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है।

### कमजोरियां

1. अर्थव्यवस्था की क्षमता के संदर्भ में उसकी एक बड़ी कमजोरी है आय एवं संपदा के पुनर्वितरण, सेवा आपूर्ति एवं बाजार विनियमन के लिए क्षमता निर्माण के संबंध में समाज की व्यापक विचारधारा, मानसिकता तथा विचार एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों तथा निजी क्षेत्र की भूमिका के संबंध में भ्रम। इतिहास से विकसित निहित स्वार्थों के साथ मिलकर इसने ऐसा सामाजिक-राजनीतिक वातावरण तैयार किया है, जो अर्थव्यवस्था की पूर्ण आर्थिक क्षमता प्राप्त करने की दृष्टि से कम अनुकूल है।

2. केंद्र तथा राज्य सरकारों के पास भरपूर पुनर्वितरण नीतियां हैं, लेकिन उनमें प्रभावी लक्ष्य निर्धारण की कमी है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन भी आवश्यकता से कमजोर संरचना एवं कार्यक्षमता के लिहाज से जटिल ढांचे से बाधित हो सकता है।

3. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं के संदर्भ में वैचारिक एवं दार्शनिक भ्रम ने बेकार की देरी करायी है और योजना से बाहर आने, सरकारी हिस्सेदारी

के विनिवेश, दखल देने वाली नीतिगत पहलों, संपदा अधिकारों की रक्षा आदि के संबंध में बहसों को जन्म दिया है।

4. विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में से स्वास्थ्य तथा शिक्षा की आपूर्ति सभी राज्यों में दोहराए जाने योग्य कोई अच्छा नमूना उपलब्ध नहीं करा पायी है। इन सेवाओं की कुशल आपूर्ति बड़ी कमजोरी रही है।

5. निजी निवेश कम है और निर्यात ऊंची दर से नहीं बढ़ रहे हैं। ये दोनों वृद्धि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन भारत में बाद में दोनों ही काफी सुस्त पड़ गए हैं।

6. कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों को दबाव भरे बहीखातों ने एक साथ जकड़ लिया है। कंपनियां नये निवेश पर खर्च करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे अपना कर्ज चुकाने में नाकाम रही हैं तथा बैंक और उधारी देने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) इकट्ठी हो गयी हैं।

7. केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि स्पेक्ट्रम, विनिवेश और सरकार को प्राप्त लाभांश से मिलने वाली प्राप्तियां अपेक्षा से कम रह गयी हैं। निकट भविष्य में भी उनके बढ़ने की अपेक्षा नहीं है।

8. राज्य सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे भी बढ़ने लगे हैं। उदय योजना का क्रियान्वयन इसका महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि इस वर्ष से सुधार की आशा है, लेकिन राज्य बॉण्डों की जनवरी 2017 में हुई नीलामी में ब्याज की लागत अक्टूबर 2016 की अपेक्षा तेजी से बड़ी है।

9. ऋण और जीडीपी के अनुपात में कमी लाने के लिए प्राथमिक घाटे को कम करने के बजाय उच्च वृद्धि दर पर अधिक निर्भरता ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को वांछित परिणाम नहीं दिए हैं।

10. विभिन्न जिलों के लिए सार्वजनिक राशि का वितरण इतना दोषपूर्ण है कि जहां गरीबों की संख्या के कारण अधिक आवश्यकता है, वहीं अधिक कमी देखी गयी है।

11. भारत में कामकाजी उम्र वाली आबादी तथा गैर कामकाजी उम्र वाली आबादी का अनुपात 2020 तक लगभग 1:1 होकर अपने अधिकतम मूल्य तक पहुंच



जाएगा। अन्य ब्रिक्स देशों में अधिकतम मूल्य की अपेक्षा यह खासा कम है, जिससे पता चलता है कि भारत में जनांकिकीय लाभांश कम है। भारत में यह अनुपात लंबे समय बाद ही अपने चरम तक पहुंचने की संभावना है।

12. हाल के वर्षों में देश में निवेश एवं बचत की दरें घटती जा रही हैं।
13. भारत में राज्यों के बीच आय एवं खपत की असमानता बढ़ती जा रही है।

### अवसर

1. फंसे हुए संसाधनों को मुक्त करने के लिए कंपनियों की निकासी के वास्ते दिवालिया कानूनों में सुधार।
2. समावेश एवं निष्पक्षता के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधार कार्ड के कानूनी आधार को मजबूत करना एवं एक-दूसरे के साथ काम करने में सक्षम बनाना।
3. प्रतिस्पर्द्धी एवं सहकारी संघवाद में कौशल, निवेश एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने की अकूत क्षमता है।
4. ढांचागत सुधारों का अधूरा एजेंडा मजबूत राजनीतिक संकल्प के बाद पूरा किया जा सकता है, विशेषकर बड़े मूल्य वाले नोटों को बंद किए जाने के बाद क्योंकि लंबे समय बाद सरकार को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है।
5. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण मजबूत होता डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात घटाने तथा घरेलू खपत को बढ़ाने पर विवश कर सकता है। इससे भारत तथा शेष विश्व पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। चीन द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए भारत समेत विभिन्न देशों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्द्धी हो सकती है।
6. अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों में उच्च वृद्धि की संभावनाएं भारत समेत विकासशील देशों से निर्यात में नई जान फूंक सकती हैं।
7. जहां तक श्रमोन्मुखी निर्यात की बात है, ब्रेक्सिट के बाद भारत के पास ब्रिटेन एवं यूरोप के साथ मुक्त व्यापार संधियों पर दोबारा बातचीत करने एवं निर्यात और

रोजगार वृद्धि से अच्छा लाभ उठाने का अवसर है।

8. क्षेत्रीय व्यापार संधियों पर अमेरिका के प्रतिकूल रुख के कारण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) तथा बहुपक्षीय व्यवस्था की प्रासंगिकता एवं प्रभाव बढ़ने की संभावना है, जिसका लाभ अंततः भारत को ही मिलेगा।
9. भारत में बड़े राज्यों की जनांकिकी में बहुत अंतर है। राज्यों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता है: प्रायद्वीपीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक तथा भीतरी राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। प्रायद्वीपीय राज्यों में उम्रदराज आबादी अधिक है, जबकि भीतरी राज्यों में युवा आबादी अधिक है। जनांकिकी अंतरों से श्रम की अधिक आवाजाही के अवसरों का संकेत मिलता है, जिनसे अधिक वृद्धि होगी और कल्याण होगा।

**अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण मजबूत होता डॉलर चीन की अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात घटाने तथा घरेलू खपत को बढ़ाने पर विवश कर सकता है। इससे भारत तथा शेष विश्व पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। चीन द्वारा छोड़े गए स्थान को भरने के लिए भारत समेत विभिन्न देशों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्द्धी हो सकती है।**

10. प्रायद्वीपीय राज्यों में जनांकिकी लाभांश 2020 के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगा, लेकिन भीतरी राज्यों में यह 2040 तक ही चरम पर पहुंच सकेगा। इस तरह देश को अधिकांश अन्य देशों की तुलना में लंबे समय तक जनांकिकी लाभांश प्राप्त होगा। इससे समय के साथ ही राज्यों के मध्य आर्थिक अंतर को भरने का स्वाभाविक अवसर भी प्राप्त होगा। यह पहलू विशेष तौर पर बताता है कि ऐसे लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए शीघ्रतापूर्वक संबंधित आर्थिक सुधार करना कितना आवश्यक है।
11. बड़े और कठिन मामले चुनकर एवं कठिन निर्णय लेकर *ट्विन बैलेंस शीट* की समस्या को सुलझाने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र संपदा पुनरुद्धार एजेंसी गठित करने का अवसर है।

### जोखिम

1. एक निश्चित समय के दौरान विभिन्न देशों के वृहद आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करते समय अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां उनकी रेटिंग सुधारने में एकसमान रुख नहीं दिखातीं। दुर्भाग्य से भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है और पिछले सात वर्षों में उसकी रेटिंग में संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान उसका प्रदर्शन बहुत सुधरा है। इससे देश में निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है।
2. संघीय लोकतंत्र में लोगों को लुभाने की प्रतिस्पर्द्धी राजकोषीय अनुशासन एवं प्रशासन के मानकों को क्षति पहुंचा सकती है।
3. वेतन वृद्धि तथा उदय बॉण्डों के कारण आयी चुनौतियां राजकोषीय अनुशासन के लक्ष्यों को बनाए रखने के मामले में राज्यों के लिए चिंता खड़ी कर रही हैं।
4. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटना-क्रम एवं वातावरण तेजी से बदलकर अलगाव तथा संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं, सेवाओं तथा श्रम के वैश्वीकरण के विरोध का रुख हावी हो रहा है। लंबे समय में 8-10 प्रतिशत सकल जीडीपी वृद्धि के लिए निर्यात में 15-20 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का भारत का एक विकल्प इससे कम हो सकता है।
5. तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें चढ़ रही हैं और जिस के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। किंतु समीक्षा में एक ओर तेल उत्पादन में कमी से होने वाली संभावित समस्याओं तथा दूसरी ओर अमेरिका में शेल गैस उत्पादन के खतरे, जिससे तेल की कीमतों पर अंकुश लग सकता है, पर इस पर कुछ नहीं कहा गया।
6. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों के कारण वैश्विक ब्याज दरें तथा मुद्रास्फीति दरें मजबूत हो रही हैं। इससे भारत में आने वाले और यहां से जाने वाली पूंजी प्रवाह पर तथा उसके फलस्वरूप निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।



7. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों के कारण डॉलर में आ रही मजबूती से युआन का अवमूल्यन होता है तो इससे चीन में बड़ा ढाँचागत परिवर्तन तथा उलटफेर हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय व्यापार तथा निवेश पर भी पड़ेगा। अमेरिका तथा चीन के बीच संभावित व्यापारिक संघर्ष से विश्व अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है।
8. विश्व का निर्यात-जीडीपी अनुपात पिछले 6 वर्षों से कम हो रहा है। ऐसे निराशाजनक माहौल में विश्व निर्यात में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
9. विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे उभरते हुए देशों से गंभीर खतरा है। ये उभरते हुए देश निर्यात होने वाली जिनसें तथा सेवाओं की व्यापक श्रेणियों में भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं।
10. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के मामले में भारतीय मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत हो रही है और इसलिए भारतीय वस्तुएं तथा सेवाएं कुल मिलाकर अपनी प्रतिस्पर्धी बढत गंवा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार जनवरी 2014 की तुलना में अक्टूबर 2016 तक इसमें 19.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे 12 प्रतिशत और समीक्षा ने 8.3 प्रतिशत बताया है। अनुमानों में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि मुद्राओं के वर्ग में भारांश अलग-अलग होते हैं। किंतु तीन अलग-अलग एजेंसियों के अनुमानों से कितना भी अंतर हो, यह स्पष्ट है कि भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर बढ़ रही है और इसलिए वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता घट रही है।
11. भारत का जनांकिकी लाभांश जल्द ही कम होने की संभावना है क्योंकि 2020 तक यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और चीन तथा ब्राजील की अपेक्षा चरम की अवधि कम होगी।
- आर्थिक समीक्षा 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत, कमजोरियों, अवसरों तथा जोखिमों या खतरों की व्यापक समीक्षा की गयी है तथा चुनौतियों से निपटने एवं कमजोरियां दूर करने के लिए सटीक सुधार सुझाए गए हैं। समीक्षा में प्रयुक्त अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित व्याख्या एवं निष्कर्षों के संदर्भ में अथवा ताकत या अवसर से संबंधित धारणा में मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समीक्षा में तर्क दिया जाता है कि 'भारत में कामकाज के लिए आंतरिक प्रवास बहुत अधिक है' किंतु अनुभवजन्य प्रमाण बताते हैं कि देश के भीतर प्रवास करने वालों का 75 प्रतिशत हिस्सा केवल चार राज्यों (दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा) में पहुंचता है तथा प्रवास पर जाने वालों में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश) की है। शेष राज्यों से बड़ी संख्या में लोग कामकाज के लिए बाहर नहीं जाते। इन राज्यों में श्रमिकों की आवाजाही अधिक नहीं है। वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही पर आधारित विश्लेषण में भी यही खामी दिखती है। इसलिए वस्तुओं, श्रम तथा पूंजी के तीव्र आंतरिक एकीकरण के कारण विभिन्न राज्यों में फैले खपत एवं आय के परिणामों के संबंध में समीक्षा जो पहली पेश करती है, वह वास्तव में कोई पहली है ही नहीं। अनुभवजन्य प्रमाणों के आवश्यकता से अधिक विश्लेषण के कारण यह पहली खड़ी हुई है। ऐसी छोटी-मोटी खामियां छोड़ दी जाएं तो समीक्षा में सराहनीय कार्य किया गया है।

## फॉर्म-IV

### योजना (हिंदी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व एवं भागीदारी तथा अन्य विवरण

- (1) प्रकाशन का स्थान : नई दिल्ली
- (2) प्रकाशन की अवधि : मासिक
- (3) मुद्रक का नाम : डॉ. साधना राउत  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (4) प्रकाशक का नाम : डॉ. साधना राउत  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (5) संपादक का नाम : ऋतेश पाठक  
राष्ट्रीयता : भारतीय  
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (6) उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों : सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001 का सम्पूर्ण स्वामित्व

में डॉ. साधना राउत एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 31.01.2017

(डॉ. साधना राउत)  
प्रकाशक